बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 95

वृद्धि को महत्त्व

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने वही किया जिसकी अपेक्षा थी। उसने लगातार तीसरी बार मानक रीपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की। पिछले दो नीतिगत निर्णयों के उलट यह एकमत से लिया गया निर्णय था क्योंकि समिति के सभी छह सदस्यों ने कटौती की वकालत की। 5.75 फीसदी की मानक दर अब बीते नौ वर्षों की न्यूनतम है। गुरुवार को रीपो दर में की गई कटौती कुछ बातों को रेखांकित करती है। वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई है और निवेश कमजोर पड़ा है। निजी खपत व्यय का लगातार कम होना भी चिंता का विषय है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत समीक्षा के बाद आयोजित सम्मेलन में यह कहकर परिदृश्य स्पष्ट कर दिया कि यह निर्णय वृद्धि और मुद्रास्फीति की चिंता को ध्यान में रखकर लिया गया है। चिंता की वजह स्वाभाविक है। आर्थिक वृद्धि अपनी गति खो चुकी है और लगातार चौथी तिमाही में धीमापन आया है। इससे मौद्रिक नीति समिति को चालू वित्त वर्ष में वृद्धि का अनुमान घटाकर 7 फीसदी करना पड़ा है। पहले यह 7.2 फीसदी था।

दरों में कटौती के अलावा भी बाजार की नजर समिति के कदमों पर थी। बाजार को उन मोर्चों पर भी प्रसन्नता ही मिली। समिति ने एकमत से अपने रुख को निष्पक्ष से समायोजन वाला कर दिया। इससे इस बात का गहरा संदेश गया कि उसकी प्राथमिकता वृद्धि की ओर है क्योंकि मुद्रास्फीति के संकेतकों के तयशुदा सीमा में रहने का अनुमान है। ऐसे में गवर्नर शक्तिकांत दास की बातों से यह भी स्पष्ट है कि दरों में कटौती का सिलसिला थमा नहीं है।

दास तथा समिति के अन्य सदस्यों ने जहां अधिकांश कदम सही उठाए हैं, वहीं इकलौती निराशा की बात यह है कि नीति में ब्याज दर के कमजोर पारेषण की समस्या का हल नहीं किया गया है। केंद्रीय बैंक स्वयं स्वीकार कर चुका है कि 50 आधार अंक की पिछली दो कटौतियों में से केवल 21 आधार अंक की कटौती का लाभ नए कर्ज लेने वालों तक पहुंचा है। ऐसे में अगर चालू वर्ष के संशोधित वृद्धि अनुमानों को भी हासिल करना है तो मौद्रिक पारेषण की प्रक्रिया का तेज होना बहुत आवश्यक है। उस संदर्भ में देखें तो बाजार को बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की उपलब्धता को लेकर आश्वस्ति से इतर किसी बड़े कदम की अपेक्षा थी। नकदी प्रबंधन ढांचे की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की घोषणा अच्छा कदम है लेकिन इससे अल्पावधि में भरोसा बढ़ता नहीं दिखता।

यकीनन सरकार को यहां अहम भूमिका निभानी होगी। आरबीआई के कदमों और बैंकों द्वारा इससे होने वाले लाभ को कर्जदारों तक नहीं पहुंचा पाना एक बड़ी समस्या है। ऐसा काफी हद तक इसलिए है क्योंकि बैंक छोटी बचत योजनाओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं जो करीब 7.7 फीसदी की ब्याज दर मुहैया कराती हैं।

कई धड़ों से यह सुझाव भी आ रहा है कि अल्प बचत दरों को 10 वर्ष के बॉन्ड के बजाय रीपो दर से जोड़ दिया जाना चाहिए। बाजार में निराशा की एक अन्य वजह रही संकट के दौर से गुजर रहे गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र को लेकर किसी विशिष्ट घोषणा का नहीं होना।

दास ने केवल यह कहा कि केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाएगा। यह भी अच्छा कदम है क्योंकि केंद्रीय बैंक को ढेरों कंपनियों को संकट से उबारने वाला नहीं माना जाना चाहिए। वह भी ऐसी कंपनियां जो जोखिम कम करने के तयशुदा मानकों में क्रियान्वयन के कारण दिक्कत में हैं।

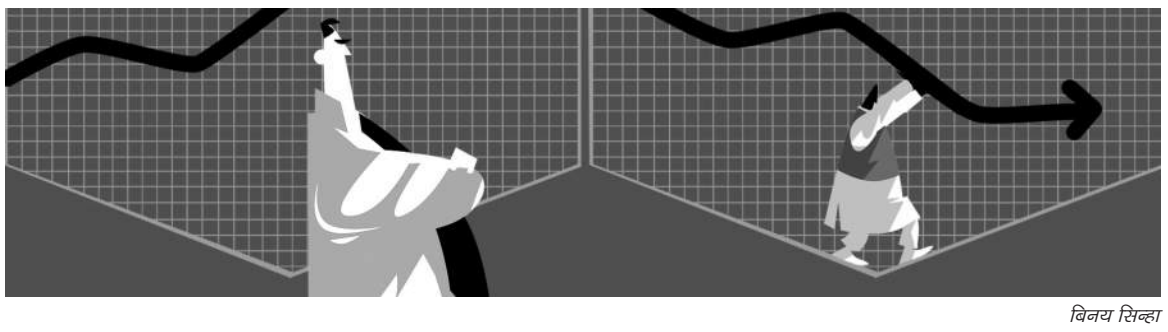

बिनय सिन्हा

नई सरकार के लिए निकट भविष्य का नीतिगत एजेंडा

बाजार प्रोत्साहनों की मांग कर रहे हैं और बड़े सुधारों को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन नई सरकार का पहला काम बुनियादी दिक्कतों को दूर करना होना चाहिए। बता रहे हैं साजिद चिनॉय

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार चुनावी जीत ने बाजारों में उत्साह भरा है और तेज वृद्धि के अगले चरण के लिए बड़े सुधारों (भूमि, श्रम, पूंजी) की उम्मीदें जगाई हैं। लेकिन नीति-निर्माताओं को बिना तैयारी के हड़बड़ी में कदम नहीं उठाने चाहिए। सबसे पहला काम मुश्किल दौर से गुजरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होना चाहिए।

पिछली कुछ तिमाहियों में वृद्धि धीमी हुई है। कुछ दबाव अल्पावधि के हैं। उदाहरण के लिए 2018-19 के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकारी खर्च में भारी कटौती, चुनाव से संबंधित अनिश्चितता और वाहन क्षेत्र में एकबारगी कीमत बढ़ोतरी। ये दबाव आने वाले महीनों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन वृद्धि का रुझान कमजोर हो गया है।

भारतीय वृद्धि केवल उपभोग रूपी एक इंजन पर उड़ान भर रही है। अब यह इंजन भी धीरे-धीरे कमजोर होने लगा है। ग्रामीण उपभोग इसलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि कृषि क्षेत्र पर असर डालने वाली वैश्विक कारोबार की स्थितियां 2018-19 में और बदतर हुई हैं। शहरी मांग में सुस्ती से एनबीएफसी, वाहन और आवास क्षेत्र में दिक्कतों का पता चलता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आय में वृद्धि धीमी पड़ने पर उपभोग के लिए बचत का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्यात का परिदृश्य भी बदतर हुआ है क्योंकि वैश्विक व्यापार युद्ध और तेज हुआ है। निर्यात और उपभोग दोनों में कमजोरी से अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पर असर पड़ने की चिंताएं पैदा हो जाती हैं।

राजकोषीय प्रोत्साहनों की मांग गैर-जिम्मेदाराना लगती हैं। क्योंकि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण की कुल जरूरत जीडीपी की करीब 9 फीसदी है। इसमें सभी घरेलू वित्तीय बचत खप जा रही हैं। इससे बाजार में ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं और ग्राहकों तक दरों में कटौती का लाभ नहीं पहुंच रहा है। किसी तरह का प्रोत्साहन देना अनुत्पादक साबित होगा। इसे ब्याज दरें और बढ़ जाएंगी, निजी निवेश में कमी आएगी और एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय संकट गहराएगा। ऐसे में नीति निर्माता मंदी को थामने के लिए क्या कर सकते हैं? हालांकि बाजार मांग पर केंद्रित हैं, लेकिन सही कदम आपूर्ति पक्ष पर ध्यान देना होगा। लघु अवधि के नीतिगत एजेंडे में तीन क्षेत्रों के अवरोधों को दूर करना शामिल होना चाहिए :

1. एनबीएफसी : नकदी नहीं, कर्ज चुकाने की क्षमता सुधरे

एनबीएफसी पिछले एक साल से भारी दबाव से गुजर रही हैं। इससे उनके ऋण बांटने में भारी कमी आई है, जिससे खपत में मंदी आई है। हालांकि ऐसे ऋण देने के लिए अब बैंक आए हैं, लेकिन वे एनबीएफसी की पूरी भरपाई नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि एनबीएफसी के कारोबारी मॉडल बहुत अलग हैं, जो अलग-अलग ग्राहकों को लक्षित करती हैं। एनबीएफसी में मंदी से अचंभित नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में वित्तीय स्थितियां बहुत विकट हो गई हैं। एनबीएफसी बॉन्डों में औसत स्प्रेड आईएलएफएस घटनाक्रम से पहले के स्तरों से काफी ऊपर पहुंच गया है। अंतरबैंक प्रणाली में नकदी की स्थिति सुधरी है, मुख्य तरलता अब अधिशेष है और बहुत सी एनबीएफसी के खातों में नकदी का स्तर काफी अधिक है। इसके बावजूद स्प्रेड में कमी नहीं आई है, इसलिए यह पहली नजर में नकदी नहीं बल्कि ऋण जोखिम का संकेत है। म्युचुअल फंडों में निवेश सूख गया है और एनबीएफसी को बैंक ऋण घट गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि बैंक भी ऋण जोखिम को लेकर सतर्क हैं। इसलिए यह नकदी की समस्या नहीं है। यह ऋण चुकाने की क्षमता की समस्या है।

नदारद मझोली एनबीएफसी?

इसमें किसी नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ऋणदाता जोखिम का फिर से आकलन कर रहे हैं और ज्यादा प्रीमियम वसूलना बाजार की वह व्यवस्था है, जो अपने आप काम कर रही है। किसी हस्तक्षेप से नैतिकता का जोखिम बढ़ेगा। इस बात की चिंताएं बढ़ रही हैं कि असंतुलित सूचनाएं आवंटन कुशलता को प्रभावित कर रही हैं। सबसे अच्छी एनबीएफसी आसानी से फंड जुटाने में सक्षम हैं और जिन पर जोखिम नजर आ रहा है, उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। समस्या दोनों के बीच बड़े अंतर की नहीं है। समस्या यह है कि 'मझोली नदारद' हैं। इस बात के आसार हैं कि मझोली एनबीएफसी पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि निवेशक उनकी संपत्ति गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं। यह असंतुलित सूचना की समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति खराब और अच्छी एनबीएफसी में अंतर नहीं कर सकता है, इसलिए सभी को ऋण देना बंद कर सकता है। इस वजह से बहुत सी एनबीएफसी नकदी जमा करने और ऋण वितरण कम करने के लिए बाध्य हो रही हैं। वे ऐसा यह दिखाने के लिए कर रही हैं कि वे खराब कंपनियों में शामिल नहीं हैं। संपत्ति गुणवत्ता को लेकर सही जानकारी न होने के कारण आवंटन में अकुशलता आ रही है। इसका ऋण, पूंजी जुटाने, ऋण बांटने और इसलिए जीडीपी वृद्धि पर असर पड़ रहा है।

सबसे बेहतर तरीका यह हो सकता है कि नियामक एनबीएफसी क्षेत्र की संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा करे। ऐसा होने से 'भरोसे की कमी' दूर हो जाएगी। इससे अच्छी एनबीएफसी इक्विट और फंडिंग जुटा पाएंगी।

2. राजकोषीय-मौद्रिक नीति की जुगलबंदी

जुलाई में विश्वसनीय बजट लाना अहम है। वर्ष 2018-19 में वास्तविक राजस्व संग्रह संशोधित अनुमानों से काफी कम रहने का अनुमान है, जिससे अगले साल अनुमानित राजस्व हासिल करना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य जीडीपी के 3.4 फीसदी को फिर से संशोधित करना चाहिए। लेकिन ऐसा विश्वसनीय रूप से राजस्व एवं खर्च का बजट बनाकर किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफसीआई जैसे वैध बजट भुगतानों को बैलेंस शीट से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

बॉन्ड बाजारों की फिर से चिंता बढ़ने के आसार हैं। बॉन्ड प्रतिफल बढ़ेगा, जिससे आगे पूंजी की लागत और बढ़ेगी। हालांकि एक भरोसेमंद बजट जीएसटी राजस्व में अहम बढ़ोतरी पर निर्भर करता है। इससे जीएसटी को और आसान बनाने और कड़ी अनुपालना व्यवस्था बनाने की जरूरत होगी।

एक भरोसेमंद बजट मौद्रिक नीति का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। पहला, यह बॉन्ड प्रतिफल को कम करेगा और वित्तीय स्थितियों को आसान बनाएगा। दूसरा, अगर बॉन्ड प्रतिफल घट जाता है तो बॉन्ड प्रतिफल से जुड़ी लघु बचत दरें भी नीचे आएंगी। इससे बैंक जमाएं और आकर्षक हो जाएंगी, जमा वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग प्रणाली में मौद्रिक नीति का लाभ ग्राहकों को मिलेगा। तीसरा, जीएसटी की गैर-अनुपालना से 2018-19 में प्रचलन में मौजूद मुद्रा (सीआईसी) में बढ़ोतरी हुई है। अगर जीएसटी की अनुपालना को सख्त बनाया जाता है तो सीआईसी की वृद्धि घटेगी, जमा वृद्धि बढ़ेगी और मौद्रिक नीति के लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाने में सहारा मिलेगा। चौथा, वृद्धि के लिए यह बहुत मायने रखता है कि राजकोषीय घाटे को कैसे पूरा किया जाता है। सार्वजनिक निवेश घटाकर घाटे को पूरा करना बनाम अप्रत्यक्ष कर संग्रह को सख्त बनाने का वृद्धि पर महत्त्वपूर्ण असर पड़ेगा।

इसके विपरीत अगर बाजार राजकोषीय विश्वसनीयता को लेकर चिंतित होते हैं और मौद्रिक नीति में ढील दी जाती है तो अल्पावधि और दीर्घावधि की ब्याज दरों में अंतर बढ़ेगा। इससे वित्तीय क्षेत्र को अल्पावधि के लिए ऋण लेने और लंबी अवधि के लिए ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन इससे वित्तीय क्षेत्र पर खतरा बढ़ेगा।

3. आयात-निर्यात के समीकरण पलटना

निकट भविष्य की तीसरी प्राथमिकता कृषि संकट से निपटना होनी चाहिए। आयात-निर्यात के समीकरण को सही बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। देश में मांग के लिए बहुत कम गुंजाइश है। पीएम किसान योजना से खाद्य की मांग बढ़ेगी, लेकिन कुल खर्च जीडीपी का महज 0.4 फीसदी है और इसके अलावा राजकोषीय गुंजाइश नहीं है। इसके बजाय जवाब आपूर्ति पक्ष में छिपा है। इस बात के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि कुछ खाद्य उत्पादों की थोक कीमतें बढ़ने लगी हैं। स्टॉक रखने की सीमा, समय-समय पर निर्यात पर प्रतिबंध और आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसी हस्तक्षेपकारी नीतियों से बचा जाना चाहिए ताकि खाद्य कीमतें सामान्य स्तर पर आएं। नई सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घरेलू स्तर पर जरूरत से अधिक आपूर्ति की स्थिति से बचने के लिए सरप्लस उत्पादन का तुरंत निर्यात किया जाना चाहिए। बाजार प्रोत्साहनों की मांग कर रहे हैं और बड़े सुधारों को लेकर उत्साहित हैं। लेकिन नई सरकार की तात्कालिक प्राथमिकता बुनियादी चीजों को दुरुस्त कर आर्थिक नाव को स्थिर करना होना चाहिए।

(लेखक जेपी मॉर्गन में चीफ इंडिया इकॉनमिस्ट हैं)

सरकारी प्रणाली के लिए ई-सुरक्षा को करें पुख्ता

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

नगर निकाय या दूसरी सरकारी प्रणाली पर साइबर हमला करना अधिक प्रचलित होता जा रहा है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके चलते नगर निकायों पर हमला करना काफी आसान हो जाता है

अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित बाल्टीमोर साइबर-रैनसम हमलों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। बाल्टीमोर नगर निकाय के तहत करीब छह लाख लोग निवास करते हैं और यह करीब 28 लाख महानगरीय समूह का एक केंद्र है। गत 7 मई को हैकरों ने नगर निकाय की कंप्यूटर प्रणाली पर हमला बोल दिया। उन्होंने अलग-अलग 10,000 कंप्यूटरों पर अपना नियंत्रण कर लिया और सर्वर तक अपनी पहुंच बना ली।

इस हमले से सरकारी ई-मेल प्रणाली ठप पड़ गई और विभिन्न विभागों के बीच ऑनलाइन भुगतान बंद हो गया। इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट के लिए लेनदेन, जीवन और मृत्यु प्रमाणपत्र आदि कई कार्य रुक गए। नगर निकाय में कामकाज जारी रखने के लिए लोगों को नकदी का सहारा लेना पड़ा।

हैकरों ने करीब एक लाख डॉलर के मूल्य के कुल 13 बिटकॉइन की मांग की जिसके बदले वे तीन मुख्य सर्वर को खोलने के लिए एक 'डिजिटल-की' प्रदान करते। नैतिकता को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय ने यह भुगतान करने से इनकार कर दिया लेकिन इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए दोबारा नई प्रणाली विकसित करने में लाखों डॉलर खर्च होंगे और इससे कार्यप्रणाली में बहुत अधिक व्यवधान भी होगा।

साल 2019 में अकेले अमेरिका के नगर निकायों पर यह 20 वां साइबर हमला था। इससे पहले मार्च 2018 में भी बाल्टीमोर पर साइबर हमला हुआ था जिसके चलते आपातकालीन नंबर 911 ने एक दिन के लिए काम करना बंद कर दिया था। इसी महीने में अटलांटा और जॉर्जिया ने साइबर हमलों में 1.7 करोड़ डॉलर गंवाए और इनसे उबरने में कई महीने लग गए।

हैकरों का तरीका बिल्कुल साधारण है। वे एक नेटवर्क में प्रवेश करते हैं और उसका डेटा एनक्रिप्ट कर देते हैं। यहां तक पहुंच बनाने के लिए कई तरीके और प्रोग्राम का सहारा लिया जाता है। इसके बाद हैकर डेटा दोबारा उपलब्ध कराने के लिए धन (विशेषकर क्रिप्टोकरेंसी के रूप में) की मांग करते हैं।

हमला झेलने वाला व्यक्ति या संस्था पूरी प्रणाली को दोबारा बनाने की लागत और हैकर को भुगतान (इस उम्मीद में कि वह आंकड़े डिक्रिप्ट कर देगा) के बारे में विचार करते हैं। हो सकता है कि संस्था के पास पूरे बैकअप के साथ डेटा रिकवरी की योजना मौजूद हो, जिससे हैकर को नजरअंदाज किया जा सके। हालांकि यह पूरी प्रणाली स्वयं काफी खर्चीली प्रणाली है।

पहले साइबर-रैनसम हमले कारोबारियों और कंपनियों पर किए जाते थे। फिलहाल नगर निकायों या दूसरी सरकारी प्रणाली पर हमला करना अधिक प्रचलित होता जा रहा है। इसके बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके चलते नगर निकायों पर हमला करना काफी आसान हो जाता है।

कारोबारी अक्सर अपने डेटा के लिए कड़ी सुरक्षा और बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। इसके विपरीत, अपनी परिभाषा की तरह, नगर निकाय की प्रणाली को सार्वजनिक संपर्क के आधार पर और कम सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाता है। इसे कई बार हजारों ऐसे कंप्यूटरों से जोड़ा जाता है जिसे कम क्षमता वाले क्लर्क ऑपरेट करते हैं। यहां तक पहुंच बनाना काफी आसान होता है। महत्त्वपूर्ण सेवाएं देने वाले किसी नगर निकाय के लिए ऑफलाइन हो जाना काफी शर्मनाक है।

इसकी तुलना में आंकड़ों का एनक्रिप्शन काफी आसान होता है। एनक्रिप्टेड आंकड़ों तक पहुंच बनाना काफी मुश्किल है। अधिकांश नए ऑपरेटिंग सिस्टम में एनक्रिप्शन स्वत: हो जाता है जिससे उपयोगकर्ता की निजता और सुरक्षा प्रभावित ना हो। हैकर मालवेयर के जरिये भी पहुंच बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि बेहतर तरीके से एनक्रिप्ट किए गए डेटा में सेंध लगाकर उसे डिक्रिप्ट करना लगभग नामुमकिन होता है।

बाल्टीमोर में 'रॉबिनहुड' रैनसम से हमला किया गया जो किसी प्रणाली को चलाने वाले सर्वर को एनक्रिप्ट कर देता है और वहां तक पहुंच बनाने के लिए डिजिटल-की की जरूरत होती है। इसके बाद ग्राहक को हैकर से संपर्क करने वाली जानकारी का एक संदेश मिलता है, जिसमें भुगतान प्रक्रिया और डिक्रिप्ट करने वाली 'की' के बारे में बताया जाता है। बिटकॉइन का चलन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस तरह की क्रिप्टोकरेंसी को ट्रेस करना काफी मुश्किल है और इसे आसानी से किसी भी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।

बाल्टीमोर वाले मामले में हैकरों ने प्रत्येक अतिरिक्त डिजिटल-की के लिए 10,000 डॉलर की मांग की थी और दावा किया था कि 10 दिन के भीतर डेटा उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि यह समयसीमा काफी पहले बीत चुकी है। शहर ने अपनी प्रणाली दोबारा विकसित की है और इस बात की भी जांच की कि मालवेयर किस तरह प्रणाली में आया था।

पूरे विश्व के नगर निकायों के लिए यह एक संदेश है। नगर निकायों को न सिर्फ सुरक्षित प्रणाली अपनानी होगी बल्कि आकस्मिक उपाय के तौर पर डिजास्टर रिकवरी प्लान भी तैयार किया जाए।

कानाफूसी

कांग्रेस को अवसर

मध्य प्रदेश में सपा और बसपा के सहारे मामूली बहुमत वाली सरकार चला रही सत्ताधारी कांग्रेस के पास अपनी स्थिति मजबूत करने का एक अवसर है। दरअसल भाजपा नेता जीएस डामोर ने रतलाम लोकसभा सीट में जीत हासिल करने के बाद झाबुआ विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। डामोर ने लोकसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया को हराया जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को पराजित किया था। अब अगर कांग्रेस झाबुआ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में जीत जाती है तो विधानसभा में उसके 115 विधायक हो जाएंगे। प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 116 विधायकों की आवश्यकता है। वहीं डामोर के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायकों की तादाद घटकर 108 रह गई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उपचुनाव में जीतकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी।

ईद मिलन

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और भारतीय जनता पार्टी के ही बिहार के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने ईद के अवसर पर अपने-अपने घर पर दोपहर भोज का आयोजन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम लोग इन भोज में शिरकत करने पहुंचे। जानकारों के मुताबिक दोनों नेताओं के यहां इस साल ईद पर पिछले साल की तुलना में अधिक मेहमान पहुंचे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने का मजाक उड़ाने पर नाराजगी जाहिर की थी। इससे संकेत लेते हुए भी बड़ी तादाद में पार्टी नेता नकवी और हुसैन के घर पहुंचे। नकवी राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है जबकि हुसैन पार्टी के प्रवक्ता हैं।

आपका पक्ष

सूखते जलाशयों से पेयजल संकट

इन दिनों पानी की समस्या से कमोबेश पूरा भारत ही जूझ रहा है। मॉनसून से पहले गर्मी की मार ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 91 जलाशय पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इन जलाशयों में पानी संग्रहित करने की कुल क्षमता 161.25 अरब घन मीटर है जबकि इनमें से करीब 31.5 अरब घन यानी 20 प्रतिशत पानी ही जलाशयों में शेष बचा है। अगर स्थितियों में बदलाव नहीं हुआ तो मॉनसून से पहले दिक्कत और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं। किसानों के खेतों से लेकर घरों में पीने के पानी की आपूर्ति तक में भारी कमी देखी जा रही है। मई के आखिरी दिनों में चेन्नई के तमाम जलाशयों के सूखने के कारण पानी की आपूर्ति में 40 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। टैंकरों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी के दाम दोगुने कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में पेयजल संकट ने किसानों पर जमकर कहर ढाया है। तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद इससे निपटने में विफलता ही हाथ लगी है। नीति आयोग के समग्र जल सूचकांक के मुताबिक भारत के 21 प्रमुख शहरों के 10 करोड़ नागरिक भू-जल की समस्या से प्रभावित होंगे। वर्ष 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी यानी तकरीबन 50 करोड लोगों को सीधे तौर पर पीने का पानी उपलब्ध होने में मुश्किल होगी। भारत सरकार ने पेयजल संकट से निपटने के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। लेकिन फिलहाल मॉनसून आने से पहले इस मंत्रालय के सामने मौजूद चुनौतियां कम होती नहीं दिख रही हैं।

केंद्र और राज्यों को जल संरक्षण नीतियों का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा

उद्देश्य कुमार, मणिपाल

दो भाषा की शिक्षा नीति ही व्यावहारिक

इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यों की समिति की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 के मसौदे से स्पष्ट होता है कि यह शिक्षा नीति किसी राज्य, भाषा विशेष, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय का ध्यान रख कर नहीं बनाई गई है। इसे भारत की भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। राष्ट्र की समग्रता को लक्ष्य करके समता, गुणवत्ता, जवाबदेही और मार्गदर्शी उद्देश्य को आधार बनाया गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर दक्षिण के कुछ नेताओं को राजनीतिक स्वार्थ भुनाने का अवसर मिल गया। तमिलनाडु की सरकारों ने हिंदी पढ़ाई की सुविधा ही स्कूलों से हटा रखी है। वहां तमिल भाषी और अन्य राज्यों से आकर वहां बसे निवासियों के बच्चे हिंदी और अपने राज्यों की भाषाओं की पढ़ाई से वंचित हैं। तीन भाषा पढ़ाने की नीति अव्यावहारिक सिद्ध हो चुकी है। पूरे देश में अंग्रेजी भाषा और उसके माध्यम से शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। भारत सरकार के कामकाज से अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाई जाए तथा भारत सरकार की सभी प्रकार की सेवाओं में अंग्रेजी भाषा में कामकाज की अनिवार्यता हटाई जाए। पूरे देश में सिर्फ दो भाषाओं मातृभाषा और आठवीं अनुसूची में से कोई एक भाषा का प्रावधान हो। यह निर्णय राज्यों की सरकारें स्वयं करें।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।